फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय और फास्ट ट्रैक न्यायालय

सन्दर्भ

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर "प्राथमिकता के आधार" पर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जघन्य अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना में उनके हस्तक्षेप की मांग की है।

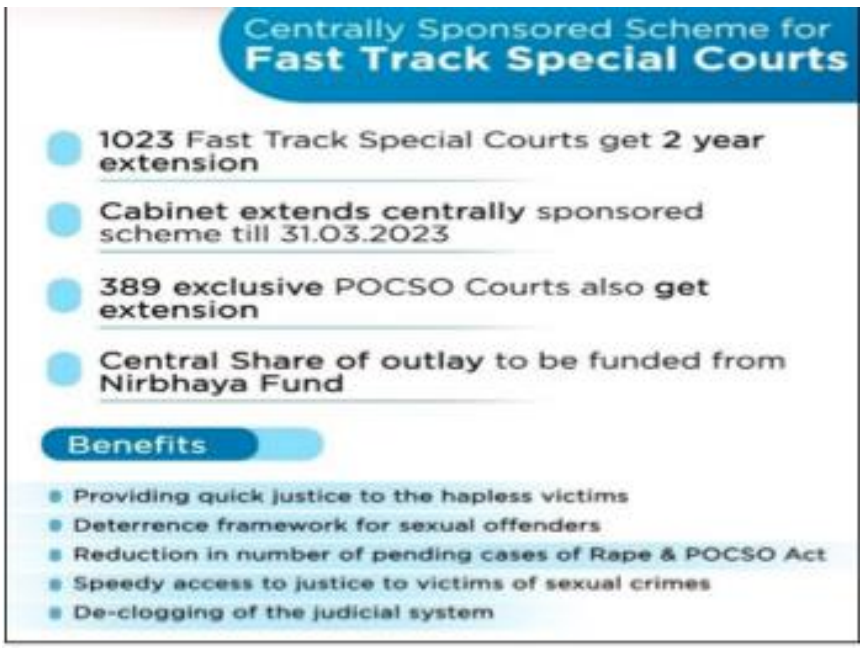

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के बारे में

- कड़े प्रावधान और त्वरित सुनवाई के लिए, केंद्र सरकार ने "आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018" अधिनियमित किया और बलात्कार के अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया।
- इसके तहत एफटीएससी की स्थापना की गयी ।
- 31 जुलाई 2022 तक, केवल 731 एफटीएससी ही चालू थे। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप को अभी इस योजना में शामिल होना बाकी है।
- इसके तहत केंद्रीय शेयर निर्भया कोष से वित्त पोषित है ।

एफटीसी के बारे में

- लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए 11वें वित्त आयोग के दौरान एफटीसी का गठन किया गया था।
- 14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान 1,800 एफटीसी स्थापित करने की सिफारिश की थी।
- 31 जुलाई, 2022 तक केवल 896 एफटीसी कार्यशील थे और इन अदालतों में 13.18 लाख से अधिक मामले लंबित थे।
- 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि स्थापित किए जाने वाले एफटीसी की संख्या राज्य के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या का 10% होनी चाहिए।
- एफटीसी की स्थापना और निधियों का आवंटन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करती हैं।
- यह जघन्य अपराधों के मामलों के लिए स्थापित किया गया है; दीवानी मुक़दमे जिसमे शामिल वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और एचआईवी-एड्स और अन्य लाइलाज बीमारियों से प्रभावित वाद और भूमि अधिग्रहण और संपत्ति / किराए के विवादों से संबंधित नागरिक विवाद जो पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं।

मर्ज

सन्दर्भ

इथेरियम ब्लॉकचैन में प्रमुख सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है, जिसे मर्ज के रूप में जाना जाता है, जिससे इसके ऊर्जा उपयोग में भारी कमी आई है।

प्रमुख बिंदु

- नई प्रणाली 99.95% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी।
- सॉफ़्टवेयर अपग्रेड से पहले, इथेरियम पर एक एकल लेन-देन में उतनी ही शक्ति का उपयोग किया जाता था, जितनी एक सप्ताह में एक औसत यू.एस. परिवार उपयोग करता है।
- मर्ज एथेरियम ब्लॉकचैन पर लेन-देन को मान्य करने के तरीके और ईथर टोकन बनाने के तरीके के लिए एक अपग्रेड है।
- अपग्रेड के साथ, एथेरियम "कार्य के साक्ष्य " प्रणाली (पीओडब्ल्यू) से "हिस्सेदारी के साक्ष्य " (पीओएस) प्रणाली में स्थानांतरित हो गया है।
- दोनों सर्वसम्मति तंत्र हैं जिसके माध्यम से ब्लॉकचेन पर लेनदेन को मान्य किया जाता है।

पीओडब्ल्यू

- पीओडब्ल्यू के लिए आवश्यक है कि नेटवर्क में कंप्यूटर रखने वाले लोगों को एक जटिल गणितीय समस्या को हल करने के लिए श्रृंखला में एक ब्लॉक जोड़ने में सक्षम होना चाहिए।
- समस्या का समाधान खनन के रूप में जाना जाता है, और 'खनिकों' को आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी में उनके काम के लिए पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन, खनन आसान नहीं है।
- गणितीय समस्या को केवल परीक्षण और त्रुटि से हल किया जा सकता है और समस्या को हल करने की संभावना 5.9 ट्रिलियन में लगभग 1 है।
- इसके लिए पर्याप्त कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है जिसके लिए काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप अधिक कंप्यूटर उपयोग अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं।

पीओएस

• यह तंत्र खनिकों को 'सत्यापनकर्ता' नामक संस्थाओं में बदल देता है।

• लेन-देन को मान्य करने का अधिकार हासिल करने के लिए इन सत्यापनकर्ताओं ने हिस्सेदारी (कम से कम 32 ईटीएच) लगाई।

• केवल शीर्ष हितधारकों को उनके कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है।

• उनका हिस्सा एक केंद्रीय वॉलेट में रखा जाता है, और उन्हें गलतियों या धोखाधड़ी के लिए दंडित किया जाता है।

• इथेरियम पीओएस अवधारणा का उपयोग करने वाला एकमात्र नेटवर्क नहीं है। हालांकि, यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी पेश करने वाला पहला था जिसने डेवलपर्स को विकेन्द्रीकृत एप्लिकेशन, डैप्स बनाने की अनुमति दी थी।

अगला उन्नयन

• इथेरियम के विलय के बाद, नेटवर्क में और भी कई उन्नयन होंगे जैसे वृद्धि , गिरावट दोषमार्जन, और बेहतरीन प्रदर्शन ।

कृतज्ञ

संदर्भ

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना और फसल विज्ञान प्रभाग के साथ 'फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन' को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 3.0 "कृतज्ञ" का आयोजन कर रही है।

प्रमुख बिंदु

• कृतज्ञ की परिभाषा है: कृ (KRI) से तात्पर्य है कृषि, त (TA) से आशय है तकनीक और ज्ञ (GYA) से तात्पर्य ज्ञान।

• इस प्रतियोगिता में देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तनकर्ता/उद्यमी आवेदन कर सकते हैं और एक समूह के रूप में कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

महत्व

• यह कार्यक्रम छात्रों/संकाय/उद्यमियों/नवप्रवर्तकों और अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवीन दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।

• इस तरह की पहल से फसल क्षेत्र में सीखने की क्षमता, नवाचार और समाधान, रोजगार और उद्यमिता के साथ वांछित तेजी से परिणाम प्राप्त होंगे। यह देश में प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों को अधिक से अधिक अपनाने को भी प्रोत्साहित करेगा।

पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ)

सन्दर्भ

- रूस ने हाल ही में सातवें पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) व्लादिवोस्तोक की मेजबानी की।
- चार दिवसीय मंच उद्यमियों के लिए रूस के सुदूर पूर्व (आरएफई) में अपने कारोबार का विस्तार करने का एक मंच है।

पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में

• ईईएफ की स्थापना 2015 में आरएफई में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।

• ईईएफ क्षेत्र में आर्थिक क्षमता, उपयुक्त व्यावसायिक परिस्थितियों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है।

• 2022 तक, इस क्षेत्र में लगभग 2,729 निवेश परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है।

• समझौते बुनियादी ढांचे, परिवहन परियोजनाओं, खनिज उत्खनन, निर्माण, उद्योग और कृषि पर केंद्रित हैं।

• चीन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेशक है क्योंकि उसे आरएफई में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पोलर सी रूट को बढ़ावा देने की क्षमता दिखाई देती है।

• इस क्षेत्र में चीन का निवेश कुल निवेश का 90% है।

• ईईएफ का प्राथमिक उद्देश्य आरएफई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना है।

• इस क्षेत्र में रूस का एक तिहाई क्षेत्र शामिल है और यह मछली, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, हीरे और अन्य खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।

• RFE को भौगोलिक रूप से एशिया में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने के लिए रणनीतिक स्थान पर रखा गया है;।

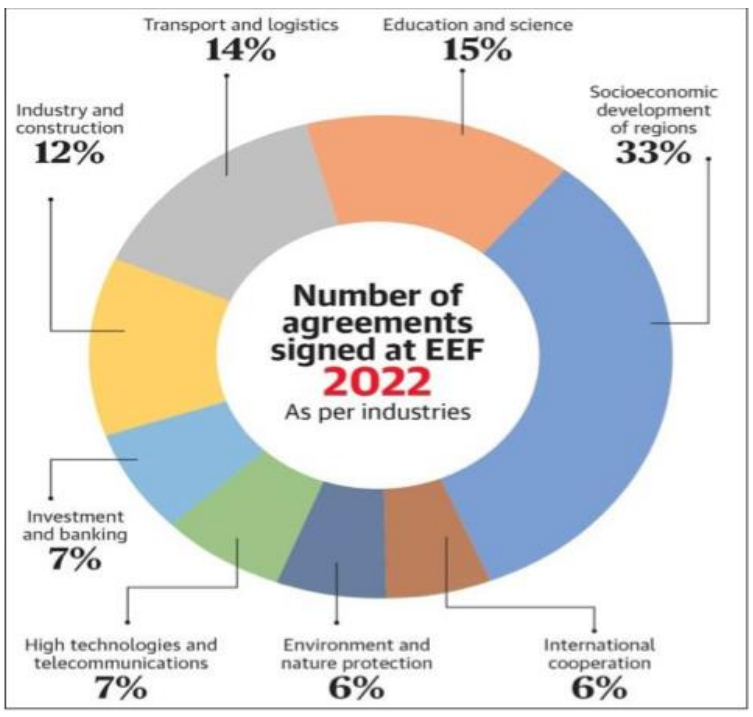

भारत का रुख

• मंच के दौरान, प्रधान मंत्री ने रूस में व्यापार, संपर्क और निवेश के विस्तार में देश की तत्परता व्यक्त की।

• भारत ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, हीरा उद्योग और आर्कटिक में अपने सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है।

• 2019 में, भारत ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $ 1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की भी पेशकश की।

ईईएफ और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ)

• अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) और ईईएफ इसके भौगोलिक कवरेज और मेजबान देशों के साथ साझेदारी के आधार पर अतुलनीय हैं।

• भारत के दोनों मंचों में निहित स्वार्थ हैं और उसने अपनी भागीदारी को संतुलित करने की दिशा में काम किया है।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड

सन्दर्भ

पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमआरडीए) की फायर ब्रिगेड ने हाल ही में एक ट्रक से हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिसाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जो पुणे से तमिलनाडु में रसायन के कंटेनर ले जा रहा था।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H_2O_2) के बारे में:

• यह एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसे आमतौर पर विभिन्न शक्तियों के जलीय घोल के रूप में उत्पादित किया जाता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है:
कपास और अन्य वस्त्रों और लकड़ी के गूदे को विरंजन करने में ,
अन्य रसायनों के निर्माण में,
एक रॉकेट प्रणोदक के रूप में, और
कॉस्मेटिक और औषधीय प्रयोजनों के लिए।

• हालांकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैर-विषैला पदार्थ होता है, लेकिन केंद्रित रूप में इसका एक्सपोजर खतरनाक होता है , यानी लगभग 8% से अधिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड युक्त विलयन त्वचा के लिए संक्षारक होते हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम

सन्दर्भ

हाल ही में कश्मीर घाटी में इस अधिनियम के तहत दो प्रमुख धार्मिक विद्वानों सहित सात मौलवियों को गिरफ्तार किया गया था।

पीएसए के बारे में

• जम्मू और कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA), 1978, एक प्रशासनिक निरोध कानून है जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या आरोप के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

• सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना वारंट, विशिष्ट आरोपों और अक्सर अनिर्दिष्ट अवधि के लिए लोगों की गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति देता है।

• पीएसए के तहत डिटेंशन ऑर्डर या तो मंडलायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है।

• इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को हिरासत में रखना सख्त वर्जित है।

• सलाहकार बोर्ड एक गैर-न्यायिक निकाय है जिसे पीएसए की धारा 14 के तहत निरोध के आदेशों की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया है कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

कुतुब शाही मकबरा

सन्दर्भ

हैदराबाद में कुतुब शाही मकबरे परिसर के अंदर छह कुओं को हाल ही में पुनर्स्थापित किया गया था जो यूनेस्को की विश्व धरोहर शहर के लिए मजबूत आधार बनाने में मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु

• पुनर्स्थापित किए गए मध्ययुगीन कुओं में 16.5 मीटर गहरे (लगभग पांच मंजिला) 3.5 मिलियन लीटर क्षमता वाली बड़ी बावली और जमशेद कुली के मकबरे के पास
एक समान रूप से विशाल बावड़ी के साथ-साथ 4.7 मिलियन लीटर क्षमता वाला हम्माम बावली शामिल हैं।

• राज्य सरकार लाड बाजार के पास जिलाउ खाना सहित पुनर्स्थापित करने की योजना बना रही है।

• 15वीं शताब्दी के कुतुब शाही मकबरे परिसर में कई मकबरे, अंत्येष्टि मस्जिद, कुएं और मनीकृत उद्यान हैं।

वर्जिन लेक

सन्दर्भ

ट्रेकिंग के प्रति उत्साही लोगों के एक समूह ने हाल ही में उत्तराखंड हिमालय में "16,500 फीट की ऊंचाई पर फ़िरोज़ा, क्रिस्टल-क्लियर पानी के साथ लगभग 160 मीटर लंबी और 155 मीटर चौड़ी एक अस्पष्टीकृत झील की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- रुद्रप्रयाग में नई झील की खोज ट्रेकर्स के लिए दर्शनीय है।
- जिले की अन्य झीलें वासुकी ताल, बासुरी ताल, देवरिया ताल, बधानी ताल, सजल सरोवर, नंदी कुंड, आदि हैं।

सोवा

सन्दर्भ

सीईआरटी-इन द्वारा जारी नवीनतम एडवाइजरी के अनुसार, एक नया मोबाइल बैंकिंग 'ट्रोजन' वायरस भारतीय ग्राहकों को लक्षित कर फैल रहा है।

- वायरस फिरौती के लिए किसी Android फ़ोन को चुपके से एन्क्रिप्ट कर सकता है और इसे अनइंस्टॉल करना कठिन है।
- मैलवेयर का पहला संस्करण पहली बार सितंबर 2021 में चोरी छुपे बाजारों में बिक्री के लिए आया था , जिसमें कुंजी लॉगिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने, कुकी चुराने और ऐप्स की श्रृंखला में नकली ओवरले जोड़ने की क्षमता थी।

ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022

सन्दर्भ

क्रिप्टो विश्लेषण प्लेटफॉर्म Chainalysis के अनुसार, उच्चतम क्रिप्टो-मुद्रा अपनाने की दर वाले 20 देशों की सूची में भारत दो स्थान गिरकर चौथे स्थान पर आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- सूची में 20 में से 18 देशों के साथ उभरते हुए बाजारों का दबदबा है।
- वियतनाम ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा और उसके बाद फिलीपींस और यूक्रेन का स्थान रहा।
- पीयर-टू-पीयर (पी2पी) एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम के मामले में भारत के खराब स्कोर ने इसकी समग्र रैंकिंग को कम कर दिया।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

सन्दर्भ

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने गुजरात में एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय के लिए रेटिंग प्रक्रिया के परिणामों को रोक दिया है।

प्रमुख बिंदु

- बेंगलुरू में स्थित, NAAC एक सरकारी संगठन है जो गुणात्मक मूल्यांकन करता है और कई मानकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को ग्रेड देता है।

- शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई, 1986) और कार्य कार्यक्रम (पीओए, 1992) ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मान्यता एजेंसी की स्थापना की वकालत की।
- नतीजतन, नैक की स्थापना 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई थी।
- 3.51 से ऊपर का ए++ ग्रेड या सीजीपीए स्कोर उच्चतम रेटिंग माना जाता है।
- नैक अपनी सामान्य परिषद (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के माध्यम से कार्य करता है। यूजीसी के अध्यक्ष एनएएसी के जीसी के अध्यक्ष हैं।

नौवीं अनुसूची

सन्दर्भ

झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित मसौदा विधेयक पर कैबिनेट नोट, 1932 को अधिवास की स्थिति निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ वर्ष के रूप में रखते हुए कहा गया है कि यह विधेयक तभी लागू होगा जब केंद्र इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन को मंजूरी देगा।

प्रमुख बिंदु

• नौवीं अनुसूची में 284 केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिन्हें अनुच्छेद 31बी के अनुसार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं कहा जा सकता है और न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं।

• संविधान के पहले संशोधन (1951) में नया अनुच्छेद 31 ए और अनुच्छेद 31 बी शामिल किया गया, जो एक साथ कृषि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित कानून की रक्षा के लिए बनाए गए थे।

• कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में, सरकार के जमीन खरीदने के उद्देश्य से जमींदारों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के फैसले की न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में आलोचना की गई थी।

• हालांकि, अदालतों ने कई बार यह माना है कि 9वीं अनुसूची में कानूनों की समीक्षा आईआर कोएल्हो 2007 के अनुसार की जा सकती है। यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, जैसा कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare